International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.9 No.6 July – Aug 2022

सहरिया विकास में विभिन्न योजनाओं का योगदान

डॉ. जितेन्द्र सिंह
सहायक–प्रध्यापक, समाजशास्त्र
अ.रा.ब.जैन विश्वभारती महाविद्यालय, छबडा।
DOI- 10.5281/zenodo.7088574

राजस्थान के हाडौती अंचल के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के गांव तथा जंगलों में सहरिया जनजाति निवास करती है जो राज्य का एक मात्र आदिम जनजाति समूह है दोनो ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित कर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र कि कुल जनसंख्या २.७३ लाख है। जिसमें से सहरिया क्षेत्र की अनुसुचित जनजाति की जनसंख्या १.०२ लाख है। जो क्षेत्र की जनसंख्या का ३७. ४४ प्रतिशत है। अज्ञानता, निरक्षरता, नशे की प्रवृति एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सहरिया जनजाति शोषित समुदाय बनकर रह गयी है। सहरिया विकास कार्यक्रम वर्ष १९७७–७८ से आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहरिया जनजाति के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के भरपूर प्रयास किये गये है।

सहरिया जनजाति के विकास एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं विशेष केन्द्रिय सहायता के रूप में संचालित की जा रही है। जिनमें मुख्य योजनाएं निम्न है–

१. शैक्षिक कार्यक्रम :–

१. आश्रम विद्यालय की स्थापना – इस योजना का शुभारम्भ १९९०–९१ में हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिये आश्रम विद्यालय बनाये गये है।

२. छात्रावास योजना – इस योजना का प्रारम्भ तृतीय पंचवर्षिय योजना के तहत किया गया । इस योजना के तहत अनुसुचित जनजातियों की बालिकाओं के लिये मिडिल और हाई स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रावास बनाये जाते हैं

३. आश्रम छात्रावासों मे विशेष कॉचिंग योजना – १०वीं १२वीं के छात्र-छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से छः माह तक कठिन विषयों की कोंचिग करवाई जाती है।

४. मुक्त स्टेस्नरी वितरण – १ से १२ वीं तक बच्चों मुक्त पुस्तकें वितरित की जाती है।

२. अन्य सामाजिक उत्थान हेतु योजनायें :-

१. कृत्रिम गृभाधान केन्द्रो का संचालन – उपलब्ध पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने व अच्छी नस्ल उत्पति हेतु कृत्रिम गृभाधान कराना।

२. ब्लास्टिंग द्वारा कृषि कुप गहरा कराना – जनजाति कृषकों कुऐं जिनका जलस्तर कम हो गया है उन्हें पुनः बढ़ाकर सिंचायी हेतु उपलब्ध कराना।

३. डीजल या विद्युत चालित पम्प सेट पर अनुदान देना।

४. कुटीर ज्योति योजना :- गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले जनजाति दस्तकारों को अधिक कार्य समय उपलब्ध कराने के निमित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना।

इन विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त भी अन्य योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। जैसे :- छात्र गृह किराया योजना, व्यावसयिक प्रशिक्षण, स्वैछिक संगठनों का अनुदान, शैक्षणिक भम्रण योजना, निःशुल्क स्कुटी वितरण योजना, मॉ-बाडी केन्द्रो का संचालन, तपेदिक नियत्रण कार्यक्रम, लघु वनोत्पदो के लिए सहायकता अनुदान कार्यक्रम, फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण, जनश्री बीमा योजना, सहरिया आवास निर्माण, सहरिया स्वास्थय सहयोगी योजना।

इस प्रकार आदिम जनजाति के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है ताकि ये आदिम समुह विकास की धारा में समाहित होकर अपना सम्पूर्ण विकास कर सके।

सन्दर्भ :-

1- tribs.gov.in
2- नरेश कुमार वैद्य (२००३), जनजातिय विकास मिथक एवं यर्थाथ, रावत पब्लिकेशन
3- वर्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन २०१०-११, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर पृष्ठ, ४६